File No. 11014/7/2022-रा.भा.(प) (Computer No. 5092)
45831/2022/PATRIKA SECTION

राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम

देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष अर्थात अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ है, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में अमृत महोत्सव की रूपरेखा भी बताई है। उनका कहना है कि-देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव कोटि-कोटि भारतवासियों का पर्व है, जिसमें पूरे भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आज़ाद भारत को गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। यह आयोजन हमारे इन 75 वर्षों की उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखने का और अगले 25 वर्षों के विकास की रूपरेखा और संकल्प के लिए प्रेरणा का अवसर है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यतया स्वतंत्रता-संग्राम, नए विचारों, उपलब्धियों, विकास-कार्यों और संकल्पों पर ज़ोर रहेगा।

स्वतंत्रता-संग्राम

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने को हैं। देश के स्वतंत्रता-संग्राम का जहाँ तक संबंध है, हमारा देश समय-समय पर अनेक भीतरी-बाहरी शक्तियों से आक्रांत होता रहा है। अनेक विदेशी आक्रमणकारी मुगल, अँगरेज आदि यहाँ पर आते रहे हैं। कुछ तो भारत को लूट-पाट कर लौट जाते रहे। अनेक यहाँ आकर अपनी जड़ों और अपने अस्तित्व-व्यक्तित्व को ही भूल गए। वे घुल-मिलकर यहीं के होकर रह गए। बाद में व्यापार और शासन करने की इच्छा लेकर फ्राँसीसी, पुर्तगाली और अँगरेज भारत में आए। इनमें आपस में भी सत्ता-संघर्ष होता रहा। अँगरेजों ने पहले इन दोनों और बाद में भारतीय शासकों को पराजित किया। अँगरेज़ों ने यहाँ के शासन-तंत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। अँगरेजी-साम्राज्य को भारतवर्ष से उखाड़ फेंकने के लिए पहली बार सामूहिक संघर्ष 1857 में किया गया। भीतरघाती देश-द्रोहियों के कारण यह संघर्ष सफल नहीं हो सका। इसके बाद अँगरेज़-राज का दमन चक्र, अन्याय, अत्याचार और भी बढ़ने लगा। वे कई तरह के कानून बनाकर हम पर बलपूर्वक लादने लगे। तब देश के बुद्धिजीवी स्वतंत्रता-प्रेमियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर अनेक प्रकार के प्रयत्न किए। कई प्रकार के आंदोलन चलाए। बदले में अँगरेजों का दमन चक्र बढ़ता ही गया। अनेक नवयुवकों को काले पानी का दंड दिया गया। कइयों को फाँसी हुई। माँ के अनेक सपूतों को जेलों में सड़ा दिया गया। अनेकों को लाठियाँ-गोलियाँ सहनी पड़ीं। असहयोग और सत्याग्रह करना पड़ा। तब जाकर देश को स्वतंत्र करा पाना संभव हुआ।

अँगरेज़ों की दो सौ वर्षों की दासता के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तब हम एक गरीब देश थे। भारत-पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका से देश जल रहा था। नागरिकों का औसत जीवन-काल उस समय मात्र 40 वर्ष ही रहता था। हमने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया था। एक ऐसा गणराज्य, जिसमें वयस्कों को मतदान द्वारा सरकार चुनने का अधिकार होगा। हमारा देश शुरू से विविधताओं भरा देश रहा, इसलिए पूरे विश्व की नजरें इस पर थी। देश ने तय किया था कि हम अपनी आवश्यकताओं और अपने आदर्शों के अनुसार इसकी स्थापना करेंगे। हमने भाषाई आधार पर राज्यों की रचना की।

स्वतंत्रता-सेनानियों और राजनेताओं ने इस बात को अच्छे से समझ लिया था कि देश को एकसूत्र में बाँधने के लिए एक राजभाषा का होना आवश्यक है। हमारे देश के संविधान-निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी यह भलीभाँति जानते थे कि देश को एकसूत्र में पिरोना निश्चित ही चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए राज्यों को अपने-अपने राज्य की राजभाषा चुनने का भी अधिकार देना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने भी यह अनुभव किया था कि देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के साथ-साथ भले ही बहुभाषी देश रहे, पर हमारी कोई एक राजभाषा अवश्य हो। विश्व कवि

Generated from eOffice by SUNITA AGNIHOTRI, ASO(PATRIKA) SA, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Official Language on 09/11/2022 10:48 AM

File No. 11014/7/2022-रा.भा.(प) (Computer No. 5092)
45831/2022/PATRIKA SECTION

वींद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का मानना था कि हम अपने देश को विश्व के सामने एक नए नजरिए से उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करें।

5 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने पूर्वजों के स्वप्न को साकार करने का आह्वान करते हुए कहा कि मातृभाषा निर्धनता से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि भाषाई बाधाओं को तोड़कर ही हर कोई प्रगति कर सकता है और अनेक युवा भाषाई बाधा के कारण अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में इस बाधा को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं में अपनी भाषा में पढ़ाई करके आत्मविश्वास जागृत हो सकता है। गरीब की बेटी और गरीब का बेटा मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल बनेंगे, तभी उनकी योग्यता के साथ सही न्याय हो पाएगा। उन्होंने खेलकूद का उदाहरण देते हुए कहा कि भाषाई जंजीरें के टूटने के कारण ही अलग-अलग पृष्ठभूमि से आकर ओलंपिक 2020 में हमारे खिलाड़ी आगे निकल पाए हैं।

उन्होंने यह भी कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद हम अन्य क्षेत्रों में भी अब तक वंचित रहे प्रतिभावान छात्रों को आगे बढ़ते देखेंगे। गरीब, ग्रामीण और जनजातीय पृष्ठभूमि वाले प्रतिभाशाली छात्र अब पीछे छूटने नहीं पाएँगे। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर स्तर तक मातृभाषा को शिक्षा और परीक्षा का माध्यम बनाए जाने से आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मातृभाषाओं में उच्च कोटि की पाठ्य सामग्री तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में इसे कार्य-योजना का एक प्रमुख बिंदु बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। कई संस्थान भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। यह भी सामने आया कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के कुछ वर्ष तक हम बुनियादी शिक्षा और भू-सुधारों के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए। आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा अवसर है, जब हम बाबा साहेब अंबेडकर, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी और नरसिम्हा गोपालस्वामी अय्यंगार आदि संविधान-निर्माताओं के स्वप्न को साकार होते देख रहे हैं।

नए विचार

देश भर की सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएँ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम, नए विचारों, उपलब्धियों, विकास-कार्यों और संकल्पों का समावेश कर कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर रही हैं। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की 70 प्रतिशत से अधिक शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। देश में बैंक के ग्राहकों की संख्या 45 करोड़ के ऊपर पहुँच गई है। बैंक ने वर्ष 1955 में अपनी स्थापना के बाद से ग्रामीण विकास के कार्यों और छोटे-छोटे ऋण वितरण कार्यक्रमों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया है। बैंक प्रमुख कृषि और औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण मुहैया कराता रहा है और देश की प्रगति में भागीदार बना है।

बैंक ने देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर घोषणा की है कि वह अपने ग्राहकों को रियायती दरों पर कर्ज देगा, कर्ज का कोई प्रक्रिया-शुल्क नहीं लेगा और निश्चित अवधि वाली जमाराशियों पर अधिक ब्याज देगा। बैंक ने अपनी एक प्रेस-विज्ञप्ति में कहा है कि अपने कार ऋण ग्राहकों को प्रक्रिया-शुल्क में छूट देगा। बैंक ने अपने कार ऋणों के लिए पंजीकरण-शुल्क और कार के मूल्य के 90 प्रतिशत तक कर्ज की पेशकश की है, जिसमें वाहन बीमा भी शामिल होगा। ग्राहक यदि बैंक के योनो ऐप के माध्यम से कार ऋण के लिए आवेदन करता है, तो उसे 25 आधार अंक की विशेष ब्याज दर रियायत भी उपलब्ध होगी। योनो के उपयोगकर्ता 7.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से कार ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

स्वर्ण ऋण लेने के इच्छुक ग्राहकों को भी 75 आधार अंक की रियायत उपलब्ध होगी और वे 7.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से गोल्ड लोन ले सकेंगे। योनो ऐप के जरिये गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों से कोई प्रक्रिया-शुल्क नहीं लिया जाएगा। बैंक ने अपने आवास ऋणों पर 31 अगस्त 2021 तक कोई प्रक्रिया-शुल्क न लगाने की भी घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि बैंक के आवास ऋण 6.70 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हैं। वैयक्तिक और पेंशन ऋण पर भी कोई प्रक्रिया-शुल्क नहीं लगाया जाएगा। कोरोना काल के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों को पर्सनल लोन पर 50 आधार अंक की रियायत उपलब्ध है, जो शीघ्र ही कार और गोल्ड लोन पर भी उपलब्ध होगी। बैंक रिटेल जमाकर्ताओं के लिए 'प्लेटिनम टर्म डिपॉजिट' भी शुरू कर रहा है। इसके तहत 75 दिन, 75 सप्ताह और 75 मास अवधि वाली मीयादी जमाराशियों पर अधिक ब्याज दर 15 अगस्त 2021 से 14 सितंबर 2021 तक की अवधि के दौरान उपलब्ध होगी। बैंक के प्रबंध निदेशक (रिटेल और डिजिटल बैंकिंग) श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी का मानना है कि इस पेशकश से ग्राहक अपने ऋणों पर अधिक बचत कर त्योहार बेहतर ढंग से मना सकेंगे।

प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के विषयों में नए विचारों की भी बात की है। पूरी दुनिया को इन दिनों कोरोना महामारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश में भी कोरोना के संकट के चलते बहुत से मजदूरों को शहरों से गाँव लौटना पड़ा। बिहार के पश्चिम चंपारण में लगभग 1 लाख मजदूरों को गाँव वापस आना

Generated from eOffice by SUNITA AGNIHOTRI, ASO(PATRIKA) SA, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Official Language on 09/11/2022 10:48 AM

File No. 11014/7/2022-रा.भा.(प) (Computer No. 5092)
45831/2022/PATRIKA SECTION

पड़ा। इन मजदूरों में अधिकांश जीन्स बनाने, सूत चुनने, कपड़े की कटाई करने और बाजार में सामान बेचने वाले थे। प्रशासन ने इन मजदूरों से कहा कि वे शहरों में अपने मालिकों से पूछें कि क्या वे अपना काम-धंधा पश्चिम चंपारण में लगाना चाहेंगे। उन्होंने इसमें अधिक रुचि नहीं दिखाई। प्रशासन ने इन मजदूरों से कहा कि वे अपना उत्पादन शुरू करें। पर इन मजदूरों के पास न तो जमीन थी और न पैसा। बिहार सरकार ने इन मजदूरों को जिला मुख्यालय बेतिया से 27 किलोमीटर दूर चनपटिया में जमीन दी। इन्हें जमीन तो मिल गई, पर अपना काम शुरू करने के लिए बहुत से अन्य संसाधनों की भी आवश्यकता थी। मजदूरों के पास मशीनें और कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। बिहार के बैंक उन्हें कर्ज देने में आगे नहीं आ रहे थे। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट ने मजदूरों की मदद करने के लिए बैंकों से आग्रह किया। उसका नतीजा यह निकला कि इन स्टार्ट अप्स को करीब 6.5 करोड़ रुपए का कर्ज बैंकों से मिला। पश्चिम चंपारण में इन दिनों 50 से अधिक स्टार्ट अप्स हैं और ये 10 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर चुके हैं। बैंकों को और शिद्दत से इन इलाकों में इस तरह के प्रयासों से जुड़ना होगा। तभी वे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास संकल्प में राष्ट्र-निर्माण के लिए और अधिक योगदान कर पाएंगे।

उपलब्धियाँ

स्वतंत्रता-प्राप्ति के इन 75 वर्षों के अनिश्चितताओं के दौर में हमारी आकांक्षाएँ चरम पर रहीं। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें भारतीयों ने कड़े संघर्ष, अथक परिश्रम एवं अपनी प्रतिभा के बल पर आज़ादी से लेकर अब तक दुनिया भर में भारत का लोहा मनवाया है। इनकी सूची बहुत लंबी है। महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, होमी जे. भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, सत्येंद्रनाथ बोस, श्रीनिवास रामानुजन, कल्पना चावला, सत्य नादेंडला, सुंदर पिचई, इंदिरा नुई आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। आधुनिक विश्व के इतिहास में पहली बार किसी देश ने लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपनाकर उन्नति की है। वह भी तब जब देश ने उपनिवेशवाद और सांप्रदायिक हिंसा के अतीत में विभाजन की विभीषिका को झेला। ब्रिटिश के आने के पहले भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इसमें बड़ा योगदान रहता था। बनारसी साड़ी, ढाका का मलमल, भदोई का कालीन, कन्नौज का इत्र, केरल-कर्नाटक का रेशम, तमिलनाडु-बिहार के छोटे उद्योग और बंगाल की सोने की कारीगरी विश्वविख्यात थी।

अँगरेज़ों की गलत नीतियों के कारण हमारे गाँव धीरे-धीरे पिछड़ते चले गए। इससे देश की अर्थव्यवस्था गिरती रही। वर्ष 1961 में हमारा सकल घरेलू उत्पाद 330 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति था, जो वर्ष 1992 में 995 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति तक ही पहुँच पाया। इस प्रकार तीन दशकों में नाममात्र 1.86 प्रतिशत की ही वृद्धि हो पाई। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1977 तक यानि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद तीन दशकों में तीन में से लगभग दो भारतीय प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर गुजर-बसर कर रहे थे। यह ज़रूर है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात भारत को अकाल का सामना नहीं करना पड़ा।

वर्ष 1999 से 2019 के बीच सकल घरेलू उत्पाद लगभग 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा। वर्ष 2011 तक गरीबी का अनुपात घटकर 22.5 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2011 में पाँच में से एक भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा था। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 में यह आँकड़ा घटकर 10 प्रतिशत के नीचे आ गया। वैश्विक महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को झटका लगा और बीते वर्ष सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 24 प्रतिशत घटी थी। अप्रैल-जून 2021 तिमाही में विकास दर 20.1 प्रतिशत रही। शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक भी पहली बार 57000 के ऊपर चला गया है। यह दर्शाता है कि भारत को एक समृद्ध राष्ट्र की ओर अग्रसर करने में अब अभूतपूर्व सफलता मिल रही है।

विकास-कार्य

प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अगले 25 वर्ष का रोडमैप देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि जब देश अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए, तो शत-प्रतिशत गाँवों में सड़कें हों, शत-प्रतिशत परिवारों के पास बैंक खाते हों, सभी लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो और उज्ज्वला योजना के तहत गैस हो। प्रधानमंत्री जी का यह भी कहना है कि अमृत काल 25 वर्ष का है। पर हमें अमृत काल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना है। हमारे पास गँवाने के लिए एक पल भी नहीं है।

प्रधानमंत्री जी ने जल-संरक्षण और हर घर को जल तथा पेय जल आपूर्ति को एक प्रमुख लक्ष्य माना है। उनका स्पष्ट संदेश है कि कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार जोर रहे। गरीबों को पोषणयुक्त चावल मिलें, चाहे यह किसी भी योजना के तहत दिया जा रहा हो। उन्होंने किसानों की भलाई के अपने संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को डेढ़ गुना किया जाए, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ती दर पर बैंक से कर्ज मिले, सौर ऊर्जा का लाभ भी किसानों को मिले और अधिक किसान उत्पादन संगठन बनें, जिनसे निश्चित ही किसानों को मदद मिलेगी।

Generated from eOffice by SUNITA AGNIHOTRI, ASO(PATRIKA) SA, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Official Language on 09/11/2022 10:48 AM

ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति के बाद भारत ने निश्चित ही प्रगति की है। उपनिवेशवाद के सौ सालों से कहीं बेहतर उन्नति रही है। आज गाँवों में बिजली है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। देश के लोगों के पास मोबाइल फोन है। सड़क, राजमार्गों के निर्माण, हवाई अड्डों और बंदरगाहों ने आम नागरिक का आवागमन आसान बनाया है।

वैश्विक वृद्धि दर के मामले में भारत का स्थान अनेक देशों से ऊपर है। भारत की जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत यानि 30 करोड़ मध्य वर्ग में आ गया है। भारत की जनसंख्या के बीच भले ही आय का बँटवारा असमान रहा है। अनेक लोगों का मानना है कि भारत के सुधारों की प्रक्रिया संकटकाल में अपेक्षाकृत अधिक तेज हो जाती है। वर्ष 1991 के सुधार भी विकट भुगतान संतुलन संकट की ही उपज थे। वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट से भारत अछूता रहा। शायद यही कारण है कि दुनिया भर में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जब तेज थी, तब भारत में राजकोषीय और मौद्रिक नीति के स्तर पर जितने सुधार अपेक्षित थे, उतनी गति से नहीं हुए। उच्च राजकोषीय व्यय और ढीली मौद्रिक नीति के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी और बैंकिंग क्षेत्र में दबाव वाले ऋणों में भारी वृद्धि हुई। ऐसे ऋणों में कमी लाने की प्रक्रिया में भारत भले ही अब जूझ रहा है, पर पिछले कुछ वर्षों में ऐसे ऋण खातों में पैसा वापस लाने में भी बैंकों ने अभूतपूर्व प्रगति की है।

संकल्प

भारत में अर्थव्यवस्था के संवाहक के रूप में देश की उन्नति को गति देने में बैंकिंग क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व परिवर्तनों को देखते हुए बैंकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे बदलते परिदृश्य के अनुरूप अपने उत्पादों, सेवाओं और परिचालनों में परिवर्तन लाएं। अन्यथा वे पीछे रह जाएँगे और धीरे-धीरे अप्रचलित हो जाएँगे। पिछले दशक में बैंकिंग उद्योग में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। परिचालनों के डिजिटलीकरण पर ज्यादा ज़ोर और बैंकों में परस्पर होड़ रही है। ऐसे में जो बैंक अपने उत्पादों, सेवाओं और परिचालन-प्रणालियों को बेहतर बनाकर तकनीकी सामर्थ्य बढ़ाते जाएँगे, वे ही अपने ग्राहकों की अपेक्षानुसार बेहतर तकनीकी सेवाएँ दे पाएँगे और उन्हें अपने साथ बनाए रख पाएँगे। शाखा बैंकिंग से आगे बढ़कर, नवोन्मेषी परिचालन अपनाकर, एंनपीए में कमी लाकर, नए ऋणियों का सही चयन करने के लिए ऋण-स्वीकृति और ऋण-वितरण के पहले ग्राहक-व्यवहार के विश्लेषणों के दौरान उनकी ईमानदारी व निष्ठा को ठीक से परखकर और मुनाफा बढ़ाकर ही बैंकिंग जगत में टिके रह पाएँगे।

तेजी से बदलते परिवेश में नए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम तथा नई चुनौतियों को ध्यान में रखकर प्रमुख कार्य-निष्पादन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना भी आवश्यक हो गया है। कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व में लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। उन्हें आय से वंचित होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य-देखभाल पर भी खर्च बढ़ रहा है। हमें अपने उत्पादों, सेवाओं और परिचालनों पर भी तदनुसार नए सिरे से विचार करना होगा। सभी क्षेत्रों, विशेषकर स्वास्थ्य-सेवा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं। बैंकों को भी इसमें विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। दैनिक परिचालनों में न उलझते हुए आने वाली चुनौतियों पर नजर रखकर दूरगामी परिणामों और लाभार्जनशीलता पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

भारत तेजी से ज्ञान आधारित समाज के रूप में विकसित हो रहा है और ग्राहकों की जानकारी बढ़ने के साथ उनका तकनीकी कौशल भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति अनभिज्ञता को समझने में देरी, शिथिलता बाद में महँगी पड़ सकती है। ग्राहकों और अन्य हितधारकों आदि से जानकारी प्राप्त करने और उनके अनुसार समय-समय पर अपने उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकी का आकलन करने की पुख्ता व्यवस्था भी विकसित करनी होगी।

स्पष्ट दिशा, मार्ग, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य-निर्धारण, परिचालन-पारदर्शिता, परखी हुई रणनीतियाँ अपनाकर ही भारतीय बैंकों का प्रतिस्पर्धा में खड़े रह पाना संभव होगा। क्षणिक निर्णय न करके दूरगामी प्रभाव वाली निर्णय-प्रक्रिया, निर्णय-प्रक्रिया के स्तरों में कमी लाना, कार्य-मूल्यांकन प्रणाली, पुरस्कार, उत्तरदायित्व और निर्णय-परीक्षा को अपनाना होगा। इस सबके लिए अपेक्षित डिजिटल टूल, गजट्स का प्रबंध करना होगा। बेहतर नियंत्रण-व्यवस्था, कार्य-आवर्तन प्रणाली का विकास भी आवश्यक होगा। तकनीकी के अधिक उपयोग के चलते व्यक्तिगत संपर्क शिथिल हुआ है। इसमें सुधार लाना भी जरूरी हो गया है। जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं दोनों के साथ बेहतर वैयक्तिक संपर्क की आवश्यकता होगी। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव मनाते समय बैंकों को यह याद रखना होगा कि वे सार्वजनिक धन के रखवाले हैं। हितधारकों का विश्वास न खोएँ। बदलते आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में परिवर्तन नहीं किया, तो अस्तित्व संकट में पड़ सकता है।

हमारी शताब्दी के प्रमुख भाषा विज्ञानी और राजनीतिक दर्शनशास्त्री नोम चोमस्की का मानना है कि भारत आज इतना शक्तिशाली बन चुका है कि वह चाहे तो चीन से भी आगे निकल सकता है। उनका कहना है कि वे कई बार भारत आए हैं। उनका अनुभव शानदार रहा है। भारत एक अद्भुत देश है। भरपूर धन-संपदा है, सांस्कृतिक रूप से धनी है। पर यह

Generated from eOffice by SUNITA AGNIHOTRI, ASO(PATRIKA) SA, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Official Language on 09/11/2022 10:48 AM

File No. 11014/7/2022-रा.भा.(प) (Computer No. 5092)
45831/2022/PATRIKA SECTION

भी देखने को मिला है कि यहाँ गरीबी भी है। इसके अपार संसाधनों को देखते हुए इस पर विश्वास करना किसी के लिए भी कठिन हो सकता है। यह दिलचस्प है कि भारत और चीन अठारहवीं शताब्दी तक विश्व के केंद्र थे। भारत के पास चीन से भी ज्यादा बड़ी शक्ति बनने की काबिलियत है, लेकिन यह एक संघर्षपूर्ण रास्ता है। भारत की बहुत समृद्ध बौद्धिक परंपरा रही है। कुछ जगहों पर गरीबी और अमीरी का भेद मिटा है। वे भारत के अन्य भागों से अलग हैं। वहाँ कोशिशें भी हुई हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक समृद्धि और तकनीकी को और बेहतर ढंग से अपनाकर भारत ठान ले, तो चीन को पीछे छोड़ सकता है।

विश्व के वर्तमान परिदृश्य पर नजर डालें, तो हम पाते हैं कि मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है-पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। विश्व की एक संस्था की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का इसी तरह दोहन होता रहा, तो कुछ ही दशकों में पृथ्वी का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। ऐसे में न केवल जीवन असंभव हो जाएगा, बल्कि प्रलय भी आ सकता है। दक्षिण एशिया तथा मध्य-पूर्व से मानव का नामो निशान मिट सकता है। युवा पीढ़ी को ही इसका समाधान खोजना होगा। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल एक सीमा में किया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। यूरोप के देशों ने निर्णय लिया है कि उनके पचास प्रतिशत संसाधन सतत विकास प्रक्रिया के लिए होंगे।

नई पीढ़ी को जिम्मेदारी के साथ इन सभी चुनौतियों का सामना करना होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने इस आवश्यकता को समझकर एक अलग संवहनीयता विभाग बनाया है। इसने अपनी कार्य-योजना में इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक कारगर उपाय किए हैं। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने,

पवनचक्कियों की स्थापना, इलेक्ट्रिक कारों का वित्तपोषण और प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाना आदि उपाय इस दिशा में कुछ बड़े कदम कहे जा सकते हैं।

कोविड महामारी के पहले भारत की विकास दर तेज गति से बढ़ रही थी। जीडीपी वृद्धि दर भी काफी ऊँची ही रही थी। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दुनिया के अन्य देशों की तरह यहाँ भी आय-असमानता की स्थिति कोरोना काल के कारण विकट हुई है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृतसंकल्प दिखाई देती है। प्रधानमंत्री जी ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस आवश्यकता को रेखांकित किया है। अमृत महोत्सव का अमृत काल सभी भारतीयों के लिए भी आह्वान है कि वे अगले 25 वर्षों में मिल-जुलकर प्रयास करें, तभी हम देश को सर्वसमावेशी विकास के पथ पर अग्रसर कर सकेंगे। स्त्री-पुरुष, शहरी-ग्रामीण, अमीर-गरीब, तकनीक-विद् और तकनीक-अनभिज्ञ के बीच की खाई को पाट सकेंगे। स्टार्ट अप्स का जैसा बोलबाला शहरों में दिखता है, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उनकी वैसी ही चमक पहुँचानी होगी। ग्रामीण और अर्ध-शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं को नए उद्यमियों, उत्पादनकर्ताओं के तौर पर विकसित करना होगा। विगत वर्षों में देखा गया है कि देश में बड़े पैमाने पर टेक्नॉलजी को अपनाया जा रहा है। इस टेक्नॉलजी के उपयोग द्वारा भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें देश की युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। बैंक विशेष रूप से देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए युवाओं में आवश्यक अनुसंधान और नवोन्मेषिता विकसित करने में योगदान कर सकते हैं। युवा पीढ़ी को केवल उत्पादक ही नहीं बनाना है, बल्कि वे ऐसे उत्पाद तैयार करें जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खड़े भी रह सकें। राष्ट्र प्रथम तभी बन सकेगा और सदैव प्रथम तभी रह सकेगा, जब भारत का हर नागरिक अपने-अपने क्षेत्र में प्रथम बनेगा। किसी कवि ने लिखा है-मुश्किलों को रौंदना, आओ अपना अंदाज़ कर लें, कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज़ कर लें। एक संकल्प आओ हम जाँबाज़ कर लें। गिरना उठना, शिखर को छूना घर-घर का रिवाज़ कर लें।

• प्रदीप कुमार भूत
उप महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त
कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई

Generated from eOffice by SUNITA AGNIHOTRI, ASO(PATRIKA) SA, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Official Language on 09/11/2022 10:48 AM